जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 28 संख्याः 336 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 5 जुलाई, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2024 चैम्पियन बनने के बाद गुरुवार को ट्रोफी के साथ घर पहुंची। टीम इंडिया ने मुंबई में मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड की। अपनी चैम्पियन टीम के खिलाड़ियों को देखने के लिए मुंबई में फैन्स और प्रशंसकों का बहुत बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। मुंबई में गुरुवार के दिन इतनी भीड़ जुटी कि मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक सड़कें भीड़ से अट गईं। गुरुवार की सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर खिलाड़ी दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे थे। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। जिसके बाद टीम मुंबई के लिए रवाना हुई, जहां रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया। मुंबई एयरपोर्ट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक भारतीय फैन्स अपने चैम्पियन्स की एक झलक पाने के लिए डटे रहे। वानखेड़े में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और जसप्रीत बुमराह ने टूर्नामेंट जीतने के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। बी.सी.सी.आई. ने भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि, 29 जून को खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराने के बाद भारतीय टीम कई दिनों तक बारबाडोस में ही तूफान के कारण फंसी रही थी। फिर, बी.सी.सी.आई. सचिव जय शाह के प्रयासों से खिताब जीतने के चार दिन बाद टीम इण्डिया दिल्ली पहुंची।

मुकेश अंबानी, सोनिया गांधी से मिलने गये, 10 जनपथ

एक घंटे की मुलाकात में राहुल व प्रियंका भी मौजूद रहे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। मुकेश अंबानी आज 10, जनपथ गए तथा सोनिया गांधी से मिले। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और देश के राजनैतिक माहौल में परिवर्तन का संकेत हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि एक घंटे की इस मीटिंग में राहुल तथा प्रियंका गांधी भी मौजूद थे।

समझा जाता है कि इस मुलाकात का सुस्पष्ट उद्देश्य गांधी परिवार को अपने पुत्र की शादी में आमन्त्रित करना था। अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इससे पूर्व हुई अपने दो बच्चों की शादियों में मुकेश अंबानी ने गांधी परिवार को आमन्त्रित नहीं किया था।

एक रोचक बात यह भी है कि इस वर्ष 9 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी की तरफ से फूलों का एक बड़ा बुके भी 10, जनपथ पर पहुँचा था। ज्ञातव्य है कि इससे चंद रोज पहले 4 जून, 2024 लोकसभा के चुनाव परिणामों की घोषणा हुई थी, जिनमें कांग्रेस की उपलब्धि उम्मीद से बढ़ कर रही थी और नरेन्द्र मोदी की भाजपा खिसक कर अल्पमत में आ गई थी।

- **हालांकि, इस मुलाकात का कारण मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की 12 जुलाई को होने वाली शादी का निमंत्रण देना बताया जा रहा है। पर, यह बात गले नहीं उतरती, क्योंकि मुकेश अंबानी की अन्य संतानों की शादी में ऐसा निमंत्रण देने की बात कभी हुई नहीं।**
- **यह ही नहीं, नौ जून को राहुल गांधी के जन्म दिन पर, मुकेश अंबानी ने भारी भरकम गुलदस्ता भेजा था।**
- **क्या, राहुल के राजनीतिक दृष्टि से बढ़ते भाव से प्रभावित होकर मुकेश उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने के प्रयास में हैं।**
- **पर, इस प्रयास का प्र.मंत्री व मुकेश अंबानी के आत्मीय संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा?**
- **साथ ही राहुल गांधी, सदा से अंबानी व अडानी को प्र.मंत्री मोदी के चहेते होकर सरकार से पूरा जायज़ व नाजायज़ लाभ लेने का आरोप लगाते रहे हैं। तो क्या अब राहुल गांधी मुकेश अंबानी के बारे में अपने विचार बदल सकेंगे?**

सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र के अति महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव भी शीघ्र ही होने हैं तथा ऐसे प्रबल संकेत हैं कि शिव सेना, शरद पवार तथा कांग्रेस की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भारी उलटफेर कर सकती है तथा सत्ता में आ सकती है। जाहिर है, मुकेश अंबानी जैसे व्यावहारिक एंव समझदार व्यवसायी के लिये यह समय अपने तौर-तरीके बदलने तथा समय के बदलाव के अनुरूप चलने का है।

100 सीटों के साथ, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तथा वे राजनीतिक आकाश पर तेजी से उभर रहे सितारे हैं। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी अडानी और अंबानी पर प्रहार करते आ रहे हैं तथा जोर देते हुए कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से इन कॉर्पोरेट्स को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जिसके परिणास्वरूप उनका व्यावसाय दिनों-दिन फल-फूल रहा है तथा वे मोटा लाभ कमा रहे हैं।

देश में इस समय इस बात पर सर्वसम्मति है कि मोदी का जादू अब उतार पर है तथा राहुल गांधी राजनैतिक सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं।

रोचक यह भी होगा कि इस मुलाकात पर नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया क्या रहती है तथा प्रधानमंत्री के साथ मुकेश अंबानी के सम्बन्धों पर इस मुलाकात का क्या प्रभाव पड़ेगा।

अडानी नरेन्द्र मोदी के प्रिय रहे हैं तथा उन्हें नम्बर एक व्यवसायी बनाने के लिये मोदी ने उनपर "आउट ऑफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडू में सभी कोचिंग व ट्यूशन सैन्टर्स पर प्रतिबंध लगाये गये

तमिलनाडू सरकार द्वारा न्यायाधीश मुरूगेसन की अध्यक्षता में गठित 14 सदस्यीय पैनल ने यह सिफारिश की है अपनी रिपोर्ट में

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। तमिलनाडू सरकार शिक्षा के अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाने का विचार कर रही है। इसके अन्तर्गत कोचिंग और ट्यूशन सैन्टर्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिनके कारण शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। नीट पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों के बाद यह मुद्दा अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर चल रहे विचार-विमर्श के मूल में कोचिंग और ट्यूशन सैन्टर्स पर प्रतिबंध लगाना है।

शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने को लेकर जस्टिस मुरुगेसम की सिफारिशों में से यह एक है। चौदह सदस्यीय पैनल की कुल 550 पृष्ठों की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को इस सप्ताह के आरम्भ में सौंपी गई।

- **पैनल की राय में कोचिंग व ट्यूशन सैन्टर की वर्तमान व्यवस्था से शिक्षा का पूर्ण व्यवसायीकरण (टोटल कमर्शियलाइज़ेशन) हो रहा है तथा पढ़ाना, जो एक पवित्र काम व जिम्मेवारी था, अब एक व्यापार बन गया है।**
- **पैनल ने यह राय दी कि, इन कोचिंग इन्स्टीट्यूट व ट्यूशन सैन्टर की, विज्ञापन देकर अपना "माल" बेचने की प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो गंभीर परिणाम होंगे।**

रिपोर्ट में पुरजोर अपील की गई है कि व्यक्ति विशेष अथवा कॉरपोरेट कम्पनियों द्वारा स्कूल और कॉलेजों के समानान्तर भौतिक अथवा वर्चूअल मोड से चल रहे सभी कोचिंग सैन्टर्स पर प्रतिबंध लगाया जाए।

रिपोर्ट में कहा गया कि "कोचिंग सैन्टर्स और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स शिक्षा को एक वस्तु मानकर अपने क्रियाकलापों का विज्ञापन करते हैं जो शिक्षा की विशिष्टता का पूर्ण अनादर है। यदि इन कुटिल चालबाजियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो स्कूल और कॉलेज अप्रासंगिक बन जाएंगे। चूंकि कोचिंग सैन्टर सरकार की किसी नियामक इकाई के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं का नियमन असंभव है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश है उपयुक्त शक्तियों वाली किसी नियामक इकाई का गठन किया जाना। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "राज्य को औपचारिक शिक्षा से संबंधित मीडिया पर आने वाले सभी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। किसी भी संस्थान द्वारा औपचारिक शिक्षा को लेकर दिया जाने वाला कोई भी विज्ञापन शिक्षा के व्यवसायीकरण के समान है तथा शिक्षा के दृढ़ एवं समय परीक्षित हित में नहीं है।"

शिक्षा पैनल ने यह सुझाव भी दिया कि तमिल भाषा को स्कूली शिक्षा में प्रथम भाषा के रुप में आवश्यक रुप से स्थान देना चाहिए और शिक्षा का माध्यम भी तमिल भाषा होनी चाहिए। मसौदा रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम लक्ष्य आधारित, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुप से जवाबदेह, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी जानकारियों से परिपूर्ण और संवैधानिक मूल्यों से युक्त होना चाहिए। पैनल ने वाजिब फिटिंग और आरामदेह यूनिफार्म्स, युवतियों की परेशानी रहित आवाजाही, हवादार टॉयलैट सहित महिला अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने की भी सिफारिश की है।

राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ दीवार की चिनाई की

नई दिल्ली, 4 जुलाई। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में मजदूरों के साथ मुलाकात की। गुरुवार को उन्हें जी.टी.बी. नगर में कुछ श्रमिकों से ना सिर्फ उनका हालचाल जाना बल्कि उनके साथ काम भी किया। राहुल गांधी उनके साथ मसाला बनाते हुए और चिनाई करते हुए दिखे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से तस्वीरें साझा करते हुए यह जानकारी दी गई।

- **रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में मजदूरों के साथ मुलाकात की। गुरुवार को उन्होंने जीटीबी नगर में कुछ श्रमिकों से उनका हालचाल जाना तथा उनके साथ काम भी किया।**

कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ लिखा, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जी.टी.बी. नगर में श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आवंटित पार्किंग जगह किसी अन्य को बेचना गलत

जयपुर, 4 जुलाई (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने अपार्टमेंट में फ्लैट के विक्रय पत्र के जरिए चार पहिया वाहन के लिए आवंटित पार्किंग की जगह में से किसी अन्य फ्लैट मालिक को भी पार्किंग के लिए जगह बेचने को गंभीर सेवादोष माना है। ऐसा करने वाले मैसर्स सोना एनक्लेव्स व निदेशक पर 16.21 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। उपभोक्ता अदालत ने विपक्षी को निर्देश दिया कि वह परिवादी को एक दिसंबर 2016 के विक्रय पत्र के जरिए जो पार्किंग सुविधा मुहैया कराई गई थी वह उसी नाम व पैमाइश में उसे मुहैया कराए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने डॉ. शिव भगवान पाण्डेय व अन्य के परिवाद को मंजूर करते हुए यह निर्देश दिया।

- **जिला उपभोक्ता न्यायालय ने इसे बिल्डर का सेवा दोष माना तथा उस पर 16.21 लाख रू. का हर्जाना लगाया।**

अधिवक्ता बनवारी लाल पारीक ने बताया कि परिवादी ने दिसंबर 20216

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हेमन्त सोरेन द्वारा पुनः मु.मंत्री पद संभालना जोखिम भरा निर्णय है?

हेमन्त की अनुपस्थिति में नियुक्त मु.मंत्री चम्पई सोरेन, पुराने वरिष्ठ नेता हैं तथा शिबू सोरेन के प्रारम्भिक मित्रों में हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमन्त सोरेन ने राज्य में अगले चार माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पूर्व सीनियर नेता चम्पई सोरेन को अपने रास्ते से हटा मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर एक सोचा-समझा राजनीतिक जुआ खेला है।

हेमन्त सोरेन ने पांच माह जेल में रहने के बाद आज फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक मनी लॉण्डरिंग केस में अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व हेमन्त ने जनवरी माह में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

जे.एम.एम. के संस्थापक शिबू सोरेन के साथ काम कर चुके चम्पई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने के अपने अलग नकारात्मक पक्ष हैं क्योंकि यह घटनाक्रम भाजपा को हेमन्त सोरेन के खिलाफ मुद्दे उपलब्ध करवा रहा है। वह यह प्रचार कर सकती है कि जेल अवधि के दौरान राज्य सरकार का बखूबी संचालन करने वाले चम्पई सोरेन जैसे सीनियर नेता को मुख्यमंत्री

- **अतः चम्पई सोरेन को हटाकर हेमन्त सोरेन का पुनः मु.मंत्री बनना, हेमन्त सोरेन पर पद लोलुपता का "चार्ज" आकर्षित करता है। भाजपा ने यह चार्ज लगाना शुरु कर दिया है।**
- **पर, यह भी सच है कि, चम्पई आदिवासी क्षेत्र तक सीमित हैं, जबकि हेमन्त सोरेन की लोकप्रियता ओ.बी.सी., एस.सी. व अन्य वर्गों में भी फैली हुई है। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने भी यह ही दर्शाया, जब इण्डिया गठबंधन ने 13 लोकसभा सीटों में से केवल 5 सीटों पर जीत हासिल की।**
- **अगर लोकसभा सीटों के परिणाम को विधानसभाओं की सीटों तक फैलाया जाए तो, भाजपा का पलड़ा भारी दिखता है। अतः हेमन्त सोरेन को पुनः मु.मंत्री बनाना सही राजनीतिक निर्णय लगता है।**
- **पर, चम्पई सोरेन को भरपूर सम्मान मिलना भी जरूरी है, अन्यथा आदिवासी क्षेत्रों में इसका उल्टा असर पड़ेगा।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री की आठ व नौ जून की रूस यात्रा में चीन के लिये मैसेज है

मोदी चीन द्वारा प्रतिपादित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (एस.सी.ओ.) का न्यौता ठुकरा कर, क्यों अनायास ही रूस गये?

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (एस.सी. ओ.) के नेताओं के कज़ाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग ना लेने का फैसला करने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को का दौरा तय है।

इस संदर्भ में, रही चूक और त्रुटियां विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से भारत का कूटनीतिक संदेश देती हैं।

इसे चीन को भारत की एक कूटनीतिक घुड़की के रूप में देखा जा रहा है। एस.सी.ओ. की स्थापना चीन द्वारा की गई थी और उसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति के साथ ही अपने एजेण्डे का बढ़ाना था। बाद में इसमें कई अन्य देशों को शामिल कर चीन ने इस प्लेटफॉर्म को उभरते एवं अन्य देशों के एक वैश्विक मंच में तब्दील करना चाहा।

- **एस.सी.ओ. का गठन किया था चीन ने सैन्ट्रल एशिया क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिये।**
- **पर, फिर धीरे-धीरे चीन एस.सी.ओ. में और सदस्य जोड़ता चला गया और अन्त में बेलारूस को सदस्य बनाना तो हद ही हो गयी थी। क्योंकि, इसके बाद तो लगने लगा था कि, एस.सी.ओ. एक "डिक्टेटर्स क्लब" है तथा चीन के राष्ट्रपति शी ने एस.सी.ओ. के सम्मेलन में साफ कहा कि एस.सी.ओ. के सदस्यों को अमेरिका व पश्चिम देशों द्वारा प्रस्तावित लिबरल प्रजातंत्रीय व्यवस्था के खिलाफ संगठित होना चाहिये।**
- **भारत को यह नीति माफिक नहीं आती, और भारत रूस के खिलाफ भी बोला था, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने पर। तथा, जब अमेरिका रूस के खिलाफ एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंध लगाता चला गया, भारत ने इस प्रतिबंधों को भी स्वीकार नहीं किया और लगातार रूस से क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर खरीदता रहा। भारत के इस मूक समर्थन से रूस भी अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर पाया।**

आतंकवाद के मुकाबले और सीमा सरक्षा की सुनिश्चितता को लेकर शुरुआत में चीन, रूस, कज़ाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान एकजुट हुए थे। बाद में भारत और पाकिस्तान तथा उसके ठीक बाद अन्य मध्यपूर्व देशों का आमंत्रित किया गया। पिछले वर्ष इस संगठन में ईरान को भी शामिल कर लिया गया।

लेकिन, वैश्विक कूटनीतिक हलकों में जिस बात को लेकर भृकुटियां तनीं, वह था रूस के कट्टर सहयोगी बेलारूस को इसमें एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना। इस अंतिम सदस्य को शामिल किए जाने के साथ ही एस.सी.ओ. वस्तुतः एक "तानाशाह क्लब" में तब्दील हो चुका है, उसके सभी सदस्य अपने-अपने देशों में एक तरह से तानाशाह हैं।

दरअसल, एस.सी.ओ. के दो अग्रणी देश रूस व चीन, इस संगठन को पश्चिमी देशों के संगठन के एक विरोधी संगठन के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं और यह रूस और चीन के संपूर्ण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 150 वकीलों ने सी.जे.आई. को पत्र लिखा

नई दिल्ली, 4 जुलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत में हो रही देरी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों के 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। पत्र में वकीलों ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर स्टे लगाने वाले जज पर भी सवाल उठाए हैं।

- **पत्र में वकीलों ने रिहाई से ऐन पहले मु.मंत्री केजरीवाल की जमानत रद्द करने व सीधे तिहाड़ जेल से सी.बी.आई. द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है।**

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)